



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 276]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

मामला सं.(सीवीडी) 05/2018

विषय : चीन जन. गण. के मूल के सैकरीन के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारीशुल्क/ सब्सिडी रोधी जांच की शुरूआत

फा. सं. 6/18/2018-डीजीएडी.—मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से कतिपय सैकरीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के सब्सिडीकरण का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

### **क. सब्सिडीकरण का आरोप**

1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न प्रदेशों की सरकारों और नगरपालिकाओं जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सार्वजनिक निकायों सहित चीन सरकार में विभिन्न स्तरों द्वारा प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडीयों से लाभ मिल रहा है। आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और संगत सरकारी एजेंसियों और लोक निकायों की अधिसूचनाओं और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों जिन्होंने ऐसी स्कीमों की विस्तृत जांच की है और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी निर्धारित की है, पर भरोसा किया है।

### **ख. परामर्श**

2. ए एस सी एम के अनुच्छेद 13 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में 20 जुलाई, 2018 को जांच पूर्व परामर्श किया गया था। चीन जनवादी गणराज्य की सरकार की टिप्पणियों को रिकार्ड में लिया गया है।

### **ग. सब्सिडी कार्यक्रम**

3. आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को चीन जन. गण. की सरकार और /या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त नीचे यथा सूचीबद्ध अनेक सब्सिडियों से लाभ मिला है। कथित सब्सिडियों में निधियों का सीधे हस्तांतरण या निधियों अथवा देयताओं का संभावित सीधे हस्तांतरण; सरकार का राजस्व जो अन्यथा बकाया था, जिसे छोड़ दिया या संग्रहित नहीं किया गया; पर्याप्त मूल्य से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं।

### **। चीन में अनुदान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम**

1. कार्यक्रम संख्या 1: राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीनीकरण परियोजनाओं कोष
2. कार्यक्रम संख्या 2: प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम
3. कार्यक्रम संख्या 3: पाटनरोधी जांच के लिए अनुदान
4. कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात सहायता अनुदान
5. कार्यक्रम संख्या 6: शेयरों की लिस्टिंग के लिए अनुदान
6. कार्यक्रम संख्या 7: गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए धन
7. कार्यक्रम संख्या 8: वित्तीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से प्रदान अनुदान
8. कार्यक्रम संख्या 9: फुयांग शहर को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न अनुदान
9. करों में 10 मिलियन आरएमबी से अधिक भुगतान करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
10. उप-अनुबंध सेवा कार्यक्रम के निर्यात के तहत अनुदान
11. उत्कृष्ट नए उत्पाद / प्रौद्योगिकी पुरस्कार के तहत अनुदान
12. प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग सिटी सरकार से निवेश अनुदान
13. उद्यम संचालन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए अनुदान
14. निर्यात क्रेडिट बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान
15. हांगजो प्रीफेक्चर और फुयांग शहर (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक आफरिंग (आईपीओ) अनुदान

**16.** कार्यक्रम संख्या 10: निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि

**17.** कार्यक्रम संख्या 13: छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए समर्थन निधि

**18.** कार्यक्रम संख्या 14: तकनीकी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के लिए धनराशि।

**19.** कार्यक्रम संख्या 15: टियांजिन बिन्हाई न्यू एरिया और टियांजिन आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में उपलब्ध सब्सिडी

**20.** कार्यक्रम संख्या 16: प्रमुख उद्योग और अभिनव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि

**21.** कार्यक्रम संख्या 17: उद्यम विकास निधि

**22.** कार्यक्रम संख्या 18: जियांगसु प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

**23.** कार्यक्रम संख्या 19: जियांगसु प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान

**24.** कार्यक्रम संख्या 21: पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार (जियांगसु)

**25.** कार्यक्रम संख्या 22: चांगजो क्यूश्यूआन जिला पर्यावरण संरक्षण निधि (जियांगसु)

**26.** कार्यक्रम संख्या 23: चांगजो प्रौद्योगिकी योजना (जियांगसु)

**27.** कार्यक्रम संख्या 24: क्यूश्यूआन जिला (जियांगसु) का उद्यम अभिनव पुरस्कार

**28.** कार्यक्रम संख्या 25: परियोजना बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता निधि

**29.** कार्यक्रम संख्या 26: एलईटीडीजेड के प्रशासन कमीशन (जियांगसु प्रांत)

**30.** कार्यक्रम संख्या 27: टियांजिन के बिन्हाई न्यू एरिया में निश्चित संपत्तियों पर त्वरित मूल्यहास

**31.** कार्यक्रम संख्या 28: एंटरप्राइज़ प्रौद्योगिकी केंद्र (जैसे टियांजिन सिटी और जिनान जिला)

**32.** कार्यक्रम संख्या 29: बीजिंग सरकारों द्वारा विकास को बनाए रखने के लिए पुरस्कार

**33.** कार्यक्रम संख्या 30: बीजिंग प्रौद्योगिकी व्यापार प्रोत्साहन केंद्र द्वारा पुरस्कार

11. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात

**34.** कार्यक्रम संख्या 33: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए दो निःशुल्क / तीन हाफ कार्यक्रम

**35.** कार्यक्रम संख्या 34: भौगोलिक स्थान के आधार पर एफआईई के लिए निर्यात-ओरिएंटेड एफआईई/आयकर लाभ के लिए कर कटौती

**36.** कार्यक्रम संख्या 35: एफआईई में अनुसंधान और विकास के लिए कर प्रतिपूर्ति

**37.** कार्यक्रम संख्या 36: विदेशी निवेशक द्वारा एफआईई लाभ के पुनः निवेश के लिए आयकर रिफंड

**38.** कार्यक्रम संख्या 38: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति

**39.** कार्यक्रम संख्या 39: केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमान्य कर छूट

**40.** कार्यक्रम संख्या 40: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां

**41.** कार्यक्रम संख्या 42: घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण खरीदने के लिए एफआईई के लिए वैट रिफंड

**42.** कार्यक्रम संख्या 43: निश्चित संपत्तियों की खरीद के लिए वैट और टैरिफ छूट

**43.** कार्यक्रम संख्या 44: पसंदीदा उद्योगों के लिए आयातित उपकरण पर वैट और टैरिफ छूट

**44. कार्यक्रम संख्या 45:** विदेशी निवेश (एफआईई) के साथ उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर)

**45. कार्यक्रम संख्या 46:** तटीय आर्थिक ओपन क्षेत्रों में स्थापित और आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्रों में एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

**46. कार्यक्रम संख्या 47:** शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

**47. कार्यक्रम संख्या 48:** एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट आयकर छूट और/या कमी

**48. कार्यक्रम संख्या 49:** एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/या कमी

**49. कार्यक्रम संख्या 50:** टैरिफ और वैल्यू-एडेड टैक्स (वैट) एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर छूट

#### III. माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात

**50. कार्यक्रम संख्या 52:** पर्यास भुगतान/इनपुट/सेवाओं से कम पर दिया गया कच्चा माल

#### IV. ऋण के रूप में अभिज्ञात

**51. कार्यक्रम संख्या 53:** नीतिगत ऋण

#### V. निर्यात क्रेडिट वित्त पोषण के रूप में अभिज्ञात

**52. कार्यक्रम संख्या 55:** निर्यात क्रेडिट सब्सिडी कार्यक्रम

**53. कार्यक्रम संख्या 56:** निर्यात-आयात बैंक ऑफ चाइना-क्रेडिट उधार से निर्यात विक्रेता के लिए क्रेडिट

**54. कार्यक्रम संख्या 57:** चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात क्रेता का क्रेडिट

**55. कार्यक्रम संख्या 58** १: चीन निर्यात और क्रेडिट बीमा निगम से निर्यात क्रेडिट बीमा

**56. कार्यक्रम संख्या 59:** चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमानी निर्यात वित्त पोषण।

**57. कार्यक्रम संख्या 60:** क्रेडिट लाइनों का प्रावधान

**58. कार्यक्रम संख्या 61:** निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिमान्य ऋण "आउटबाउंड निवेश के लिए बाह्य (वैश्विक)" रणनीति

#### VI. इक्किटी निवेश के रूप में पहचाना गया

**59. कार्यक्रम संख्या 64:** इक्किटी स्वैप के लिए ऋण

**60. कार्यक्रम संख्या 65:** इक्किटी निवेश

**61. कार्यक्रम संख्या 66:** अप्रदत्त लाभांश

- यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि उनमें चीन जनवादी गणराज्य सरकार या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों से सार्वजनिक निकायों से वित्तीय अंशदान शामिल हैं और प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करते हैं। उनके आयातित वस्तुओं के मुकाबले घरेलू वस्तुओं के प्रयोग से जुड़े और/या निर्यात प्रदर्शन से जुड़े और/या कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूह और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित घरेलू वस्तुओं के उपयोग से जुड़े होने का आरोप है और इसलिए ये विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क योग्य हैं।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध और मौजूद पाया जाता है।

### घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

6. आवेदक ने नियमों में अधीन यथा विहित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मानदंडों के बारे में जानकारी दी है। आवेदक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात न केवल समग्र रूप से बढ़ा है, बल्कि भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी उसमें वृद्धि हुई है, और आयात की कीमतों में काफी गिरावट आई है। कथित सब्सिडी वाले आयातों से कीमतों में गिरावट आई है, जिससे घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। अप्रयुक्त क्षमता, लाभ, निवेश पर आय, नकदी प्रवाह में कमी और मालसूची में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन विकृत हो गया है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को 'क्षति' चीन जनवादी गणराज्य से सब्सिडी प्राप्त आयात के कारण हुई है।

### इ. जांच की शुरूआत

7. और यतः, प्राधिकारी पाते हैं कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादन या निर्यात पर पर्याप्त प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी की मौजूदगी का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस तरह के सब्सिडीप्राप्त आयात घरेलू उद्योग को उसकी मात्रा और मूल्य प्रभाव के माध्यम से वास्तविक क्षति का कारण बन रहे हैं।

8. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी संबंधित नियमावली के नियम 6 के अनुसार कथित सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं, ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### च. घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा आवेदक ने संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. ए.एस. कैमोफार्मा प्रा. लि. और मै. ब्लू सर्किल आर्गेनिक्स प्रा. लि. ने इस आवेदन का समर्थन किया है। मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नियम 2 (घ) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 2 (घ) और नियम 6 (3) के संदर्भ में योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

### छ. विचाराधीन उत्पाद

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सैकरीन" है। "सैकरीन" एक गैर-न्युट्रिटिव स्वीटनर है और उसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो प्रकार के सैकरिन होते हैं अर्थात् विलेय और अविलेय। बाजार शब्दावली में विलेय सैकरिन को सोडियम सैकरिन कहा जाता है जबकि अविलेय सैकरिन को सैकरीन या सैकरीन एसिड कहा जाता है। सोडियम सैकरीन के अलावा, सैकरीन के अन्य रूप हो सकते हैं जैसे कैल्शियम और जिंक सैकरीन। सैकरीन को दो भौतिक रूपों में उत्पादित किया जाता है अर्थात् दानेदार और पाउडर। सोडियम सैकरीन को दानेदार रूप में उन स्थितियों

में प्रयोग किया जाता है जहां सैकरिन घुल जाती है, पाउडर रूप जिसे पीसा और स्प्रे ड्राई किया जाता है को शुष्क मिश्रणों और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा विलेय होता है। सैकरिन का अविलेय रूप अनेक भेषजों और चिकित्सीय अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। सैकरिन को अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि। सैकरिन चीनी से 500 से अधिक गुना मीठी होती है। सैकरिन की सभी किस्में वर्तमान जाँच के दायरे के भीतर हैं।

- विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष सं. 29251100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

#### ज. समान वस्तु

- आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु समान वस्तु है। यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

#### ज्ञा. शामिल देश

- वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य (जिसे संबद्ध देश भी कहा गया है) है।

#### ज. जाँच अवधि

- वर्तमान जाँच में जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2017 – मार्च 2018 (12 महीने) की है। क्षति जाँच अवधि में 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 और जाँच अवधि शामिल होगी।

#### ट. प्रक्रिया और सूचना प्रस्तुत करना

- संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातिकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जाँच में भाग लेने का इच्छुक कोई पक्षकार निम्नलिखित पते पर लिख सकता है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**  
**वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110011**

- संबंधित नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिकी उत्पादकों और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

### ठ. समय-सीमा

17. वर्तमान जांच संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि चीन की सरकार, निर्यातिक और आयातक जिन्हें अलग से लिखा गया है, को उन्हें अलग से प्रेषित पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि समय-सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

### ड. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिकॉर्ड छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्वक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **ढ. असहयोग**

24. नियम 7(8) के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

### **ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

25. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2018

**Case No. (CVD) 05/2018**

**Subject: Initiation of Countervailing Duty/ Anti-subsidy investigation concerning imports of Saccharin originating in the People's Republic of China.**

**F. No. 6/18/2018-DGAD.**—Whereas, M/s Swati Petro Products Private Limited (hereinafter referred to as the applicant or petitioner) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of certain Saccharin (hereinafter referred to as the subject good), from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in the subject country.

### **A. ALLEGATION OF SUBSIDIZATION**

1. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in People's Republic of China have benefited from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of China, including the Governments of the different Provinces and Municipalities in which the producers/exporters are located, and other 'Public Bodies'. The applicant has relied upon the relevant Laws, Rules, Regulations and other Notification of the relevant Government Agencies and Public Bodies in China as available in the public domain and in the findings of other investigating authorities who have conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

## **B. CONSULTATION**

2. In terms of Article 13 of ASCM pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of the People's Republic of China on 20th July, 2018 in New Delhi. The comments of the Govt. of People's Republic of China have been taken on record.

## **C. SUBSIDY PROGRAMS**

3. The *prima facie* evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the People's Republic of China have benefited from a number of subsidies granted by the Government of the People's Republic of China and/or other public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; Provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

### **I. Identified Programs in the Form of Grants in China**

1. Program No. 1: The State Key Technology Renovation Projects Fund
2. Program No. 2 : Famous Brands Program
3. Program No. 3: Grants for Antidumping Investigations
4. Program No. 5: Export Assistance Grant
5. Program No. 6: Grants for Listing Shares
6. Program No. 7: Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province
7. Program No. 8: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
8. Program No. 9: Various grants provided to Fuyang City
9. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
10. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
11. Grants under Excellent New Products/Technology Award
12. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
13. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
14. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
15. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
16. Program No. 10: International Market Fund for Export Companies
17. Program No. 13: Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
18. Program No. 14: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprises.
19. Program No. 15 : Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
20. Program No. 16: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
21. Program No. 17: Enterprise Development Funds
22. Program No. 18: Direct Government Grants given by Jiangsu Province
23. Program No. 19: Grants under the Science and technology Program of Jiangsu Province
24. Program No. 21: Environment Protection Award (Jiangsu)
25. Program No. 22: Changzhou Qishuyan District Environmental Protection Fund (Jiangsu)

26. Program No. 23: Changzhou Technology Plan (Jiangsu)
27. Program No. 24: Enterprise Innovation Award of Qishuyan District (Jiangsu)
28. Program No. 25: Support Funds for Construction of Project infrastructure
29. Program No. 26: Administration Commission of LETDZ (Jiangsu Province)
30. Program No. 27: Accelerated Depreciation on Fixed Assets in Binhai New Area of Tianjin
31. Program No. 28: Enterprise Technology Centers (e.g. Tianjin City and Jinnan District)
32. Program No. 29: Award for Maintaining the Growth by Beijing Governments
33. Program No. 30: Award by Beijing Technology Trading Encouraging Centre

## **II. Identified in form of Tax and VAT incentives**

34. Program No. 33: Two Free/Three Half Program for Foreign Invested Enterprises
35. Program No. 34: Tax Reductions for Export-Oriented FIEs / Income tax benefit for FIEs based on geographical location
36. Program No. 35: Tax Offsets for Research and Development at FIEs
37. Program No. 36: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investor
38. Program No. 38: Preferential Income Tax Policy for Enterprises in the Northeast Region
39. Program No. 39: Preferential Tax exemptions for Central & Western Regions
40. Program No. 40: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
41. Program No. 42: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment
42. Program No. 43: VAT and Tariff Exemptions for Purchases of Fixed Assets
43. Program No. 44: VAT and Tariff Exemptions on Imported Equipment for Favored Industries
44. Program No. 45: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
45. Program No. 46: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
46. Program No. 47: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
47. Program No. 48: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
48. Program No. 49: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
49. Program No. 50: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas

## **III. Identified in form of provision for Goods and Services**

50. Program No. 52: Raw material for less than adequate remuneration /inputs/services

## **IV. Identified in form of loans**

51. Program No. 53: Policy Loans

#### **V. Identified in form of Export Credit financing**

- 52. Program No 55: Export Credit Subsidy Programs
- 53. Program No. 56: Export Seller's Credits from Export-Import Bank of China- Credit Borrowing
- 54. Program No 57: Export Buyer's Credit from Export-Import Bank of China
- 55. Program No.58: Export Credit Insurance from the China Export and Credit Insurance Corporation
- 56. Program No. 59: Preferential Export Financing from the Export-Import Bank of China.
- 57. Program No 60: Provision of Credit Lines
- 58. Program No. 61: Preferential loans provided by the Export-Import Bank "going out (global)" strategy for outbound investment

#### **VI. Identified in form of equity infusions**

- 59. Program No. 64: Debt for equity swaps
- 60. Program No. 65: Equity infusions
- 61. *Program No. 66: Unpaid dividends*

4. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of the People's Republic of China or other Regional or local governments, including public bodies and confer a benefit to the recipient. They are alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance and/or limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions, and therefore, specific and countervailable.

5. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

#### **D. ALLEGATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

6. The applicant has furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under Rules. The evidence provided by the applicant *prima facie* shows that the imports from subject country have increased, not only in absolute terms, but also in relation to production and consumption in India, and the import prices have significantly declined. Alleged subsidized imports appear to have caused price depression leading to losses for the domestic industry. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of underutilization of capacities, profits, return on investments, cash flow and significant increase in inventory. The Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence that the 'injury' to the domestic industry has been caused by subsidized imports from People's Republic of China.

#### **E. INITIATION OF THE INVESTIGATION**

7. And whereas, the Authority finds that there is sufficient *prima facie* evidence of existence of significant countervailable subsidies on production and export of the subject goods in People's Republic of China and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects.

8. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury to the domestic industry in terms of the Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **F. DOMESTIC INDUSTRY**

9. The application has been filed by M/s Swati Petro Products Private Limited. As per the evidence available on record, production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. Further the applicant has not imported nor is related to any importer or exporter of the subject goods. The application has been supported by M/s Shree Vardayini Chemical Industries Pvt. Ltd, M/s A.S. Chemopharma Pvt. Ltd and M/s Blue Circle Organics Pvt. Ltd. M/s Swati Petro Products Private Limited constitute the “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of Rules and the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the Rules.

#### **G. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

10. The product under consideration in the present investigation is “Saccharin”. Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Apart from sodium saccharin, saccharin can have other variants such as calcium and zinc saccharin. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.
11. The product under consideration is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs subheading no. 29251100 of the Customs Tariff Act, 1975. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

#### **H. LIKE ARTICLES**

12. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject good originating in or exported from People’s Republic of China. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from People’s Republic of China. The applicant claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject good produced by the domestic industry are being treated as ‘like articles’ of the subject good imported from People’s Republic of China.

#### **I. COUNTRY INVOLVED**

13. The country involved in the present investigation is People’s Republic of China (also referred to as Subject Country).

**J. PERIOD OF INVESTIGATION**

14. The Period of Investigation (POI) in the present investigation is April 2017-March 2018 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.

**K. PROCEDURE & SUBMISSION OF INFORMATION**

15. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may also write to:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Trade Remedies**  
**Department of Commerce**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi – 110011**

16. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

**L. TIME LIMIT**

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of China, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

**M. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS**

18. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked-out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

**N. NON COOPERATION**

24. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

**O. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

25. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General**